डिजिटल लत और बढ़ता संकट

असल में युवा वर्ग सूचनाओं के बोझ से दबा जा रहा है और उसके खुद के सोचने और समझने की क्षमता कम होती जा रही है, साथ ही काम में मौलिकता का अभाव स्पष्ट रूप से दिख रहा है। साइबर लत से छुटकारा पाने के लिए सरकार के साथ सामाजिक व पारिवारिक स्तर पर पहल करनी होगी और यह प्रण लेना होगा कि छोटे बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रखा जाए।

सूचना तकनीक व इंटरनेट ने विकास में बड़ा योगदान दिया है, लेकिन अब इसके भारी दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं, मसलन इंसान तकनीक का गुलाम बनता जा रहा है। बच्चों का बचपन इंटरनेट की गिरफ्त में आ चुका है। बाजार ने बच्चों के लिए भी इंटरनेट पर इतना कुछ दे दिया है कि वे पढ़ाई के अलावा और भी बहुत कुछ इंटरनेट पर कर रहे हैं। पिछले दिनों दिल्ली पुलिस और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की 'बिहेवियर एडिक्शन यूनिट' ने मिल कर एक सर्वे किया था। इसमें यह चौंकाने वाला यह तथ्य सामने आया कि स्कूलों में पढ़ने वाले हर पांच में से एक छात्र प्रोब्लेमेटिक इंटरनेट यूजर यानी 'पीआइयू' का शिकार है। इंटरनेट गेमिंग, सर्फिंग या सोशल नेटवर्किंग साइटों के दीवाने बच्चों की इंटरनेट के प्रति ऐसी लत इनकी पढ़ाई और सामाजिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। सर्वे के मुताबिक 37 फीसद छात्र अपने मिजाज व पढ़ाई के दबाव से ध्यान हटाने के लिए इंटरनेट का सहारा ले रहे हैं। इस सर्वे में दिल्ली के 25 नामी स्कूलों के कुल 6291 छात्रों ने हिस्सा लिया था। इनमें कक्षा छह से लेकर बारहवीं तक के छात्रों को शामिल किया गया था। सर्वे छात्रों के इंटरनेट इस्तेमाल करने की आदत को लेकर था।

पिछले दिनों फ्रांस की संसद ने कानून बना कर देश के प्राथमिक और जूनियर हायर सेकंडरी स्कूलों में बच्चों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी थी। इसके बाद दुनियाभर में इस पर बहस शुरू हो गई। कई लोग स्कूल में मोबाइल के फायदे गिना रहे हैं, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मक्रों ने विभिन्न सर्वेक्षण रिपोर्ट को आधार बना कर स्कूल में बच्चों के सेलफोन के इस्तेमाल पर पाबंदी का बिल खुद पेश किया और सांसदों से इसके लिए समर्थन मांगा था। फ्रांस जैसे विकसित देश के इस कदम से भारत में भी कुछ लोग ऐसी पाबंदी के कानून की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां स्कूलों में मोबाइल के दुरुपयोग के मामले बढ़ते जा रहे हैं। स्कूली बच्चों के यौन शोषण से तैयार अश्लील वीडियो क्लिप से इंटरनेट संसार भरा पड़ा है। असल में कम उम्र के बच्चे क्लास में फोन लेकर बोर्ड और पुस्तकों के स्थान पर मोबाइल पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वे एक-दूसरे को संदेश भेज कर बातें करते हैं या फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं।

इस लत से उनके सीखने और याद रखने की गति तो प्रभावित हो ही रही है, स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। अब वे खेल के मैदान में पसीना बहाने के बजाय आभासी दुनिया में व्यस्त रहते हैं। इससे उनमें मोटापा, आलस्य, आंखें कमजोर होना, याददाश्त कमजोर होने जैसे भी प्रभाव दिखने लगे हैं। पहले बच्चे गिनती, पहाड़े, स्पेलिंग या तथ्य को अपनी स्मृति में रखते थे, लेकिन अब वे हर काम के लिए सर्च इंजन का उपयोग कर लेते हैं। इसलिए भारत में कम से कम आठवीं कक्षा तक मोबाइल प्रतिबंधित करने की बात उठती रही है। डिजिटल लत की वजह से लोग वास्तविक समस्याओं से कट रहे हैं, मौलिक चिंतन और मौलिक सोच कम हो रही है, साथ ही लोगों का सामाजिक दायरा भी कम हो रहा है। भारत में भी बेंगलुरु, दिल्ली सहित कई शहरों में ऐसे केंद्र खोले जा रहे हैं जहां जिंदगी को ऑफलाइन बनाने पर काम किया जाता है।

इंटरनेट की लत एक ऐसी मनोस्थिति है, जब लोग घंटों ऑनलाइन गेम, नेट सर्फिंग या सोशल साइटों पर समय बिताने लगते हैं और इंटरनेट नहीं मिलने पर बेचैन या अवसाद से ग्रस्त हो जाते हैं। असल में युवा वर्ग सूचनाओं के बोझ से दबा जा रहा है और उसके खुद के सोचने और समझने की क्षमता कम होती जा रही है, साथ ही काम में मौलिकता अभाव स्पष्ट रूप से दिख रहा है। मशहूर लेखक निकोलस कार ने मानव मन-मस्तिष्क पर इंटरनेट के प्रभाव विषय पर अपनी चर्चित पुस्तक ह्यद शैलोजह्ल में कहा है, 'इंटरनेट हमें सनकी बनाता है, तनावग्रस्त करता है, हमें उस ओर ले जाता है जहां हम इस पर ही निर्भर हो जाएं।' भारत दुनिया के सबसे ज्यादा बेरोजगारों का देश बन गया है। बेरोजगारी के इन भयावह आंकड़ों के बावजूद युवाओं में बड़े पैमाने पर बेचैनी नहीं दिखती तो इसकी एक वजह सोशल मीडिया और डिजिटल लत भी है।

यह ठीक वैसे ही है जैसे शरीर के किसी हिस्से में दर्द होने पर दर्द का जड़ से इलाज करने के बजाय फौरी राहत के तौर पर दर्द की दवा या इंजेक्शन देकर मरीज को रहत दी जाए। लेकिन सच्चाई है कि यह राहत भी अस्थायी है और जैसे ही कुछ घंटों में दवा का असर कम होगा फिर से मूल समस्या उभर आएगी। आज युवाओं को एक सोची-समझी रणनीति के तहत बुनियादी चिंताओं से दूर किया जा रहा है या कहें कि उन्हें वास्तविक समस्यायों का अहसास भी होने नहीं दिया जा रहा है। डिजिटल लत की वजह से एक पीढ़ी के रूप में भी हम अपने जीवन पर से नियंत्रण खो रहे हैं। भारत में बेहद सस्ती दरों पर उपलब्ध डाटा की वजह से कम आय वर्ग वाले लोगों के पास भी स्मार्टफोन उपलब्ध है, जिसका सदुपयोग होने के बजाय दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। एक सर्वे के अनुसार करीब 92 प्रतिशत गरीब किशोर इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं और 65 फीसद के पास स्मार्टफोन है। वहीं, अच्छी कमाई वाले घरों के सनतानवे प्रतिशत बच्चे इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और 69 फीसद के पास स्मार्टफोन है। कई बार ऐसी लत के शिकार लोगों को पता भी नहीं चलता कि वे कब और कैसे इसकी गिरफ्त में आ गए।

बिना मोबाइल या फोन के एक पूरा दिन बिताने की कल्पना अब बहुत मुश्किल लगती है, कुछ के लिए तो शायद असंभव! हाल में ही पोलैंडवासियों ने 'डे विदआउट सेलफोन' अभियान के तहत पूरा दिन बिना मोबाइल के बिताया था। वहां लोगों को वास्तविक दुनिया से परिचित कराने और फोन पर संदेशों के आदान-प्रदान की जगह आमने-सामने बैठ कर रिश्तेदारों व दोस्तों से बात करने का मौका देने के लिए अभियान चलाया गया। इसमें पोलैंड के लोग खूब रुचि दिखा रहे हैं। असल में पोलैंड के ज्यादातर नौजवान कक्षाओं के साथ-साथ खाना खाते व सिनेमा देखते वक्त भी फोन का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से देश में फोनोलिज्म यानी फोन की लत की बीमारी में इजाफा हुआ है, ऐसे में इस तरह के अभियान की पहल की गई।

आज सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि युवाओं के अलावा कम उम्र के बच्चे भी अब डिजिटल लत के शिकार हो रहें हैं। वैसे तो साइबर लत की समस्या पूरी दुनिया में फैली हुई है, लेकिन दुनिया में युवाओं की सबसे बड़ी आबादी वाले भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह समस्या ज्यादा गंभीर है। समय आ गया है जब इसका समाधान तलाशा जाए नहीं तो यही मानव संसाधन सबसे ज्यादा दिग्भ्रमित होगा। साइबर लत से छुटकारा पाने के लिए सरकार के साथ सामाजिक व पारिवारिक स्तर पर पहल करनी होगी और यह प्रण लेना होगा कि छोटे बच्चों को घर और स्कूल में मोबाइल फोन से दूर रखा जाए। भारत में भी 'डे विदआउट सेलफोन' जैसे अभियान चलाने की जरूरत है।

प्रीती भट्ट
(स्वतंत्र लेखाकार)

सम्पादकीय

जनप्रतिनिधियों की भीड़ के सहारे गुंडागर्दी को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए

ार में भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय की ओर से नगर निगम के कर्मियों से मारपीट का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के विधायक नीतेश राणे की ओर से एक इंजीनियर से बदसलूकी का मामला सामने आ गया। इन दोनों घटनाओं के साथ तेलंगाना की उस शर्मनाक और भयावह घटना को भी नहीं भुलाया जा सकता जिसमें टीआरएस विधायक के भाई ने भारी भीड़ जुटाकर वन विभाग की महिला अधिकारी को घेरकर पीटा था।

तीनों मामले लोकतंत्र, राजनीति और जनप्रतिनिधियों को शर्मिंदा करने के साथ ही विधि के शासन का उपहास उड़ाने वाले हैं। इन तीनों मामलों में यह देखने को मिला कि जो सरकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधियों की हिंसा का शिकार बने वे अपना काम करने में लगे हुए थे। इंदौर में नगर निगम कर्मचारी एक जर्जर मकान को गिराने गए थे, लेकिन भाजपा विधायक को यह रास नहीं आया और वह उन्हें बल्ला लेकर पीटने लगे। तेलंगाना के आदिलाबाद में टीआरएस विधायक के भाई एवं जिला परिषद के अध्यक्ष कोनेरू कृष्णा ने वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने गईं महिला वन अधिकारी पर लाठियां बरसाकर उन्हें मरणासन्न कर दिया। महाराष्ट्र में मुंबई-गोवा हाईवे के पास कांग्रेसी विधायक ने अपने समर्थकों के साथ एक इंजीनियर को घेरकर पहले उन पर कीचड़ उड़ेला और फिर उन्हें खंभे से बांधने की कोशिश की। क्या ऐसी हरकतों को गुंडागर्दी के अलावा और कुछ कहा जा सकता है? आखिर जब जनप्रतिनिधि इस तरह खुली गुंडागर्दी करेंगे तब फिर आम लोगों से यह अपेक्षा कैसे की जा सकती है कि वे कानून के शासन के प्रति समर्पित रहेंयह महज दुर्योग नहीं हो सकता कि बीते कुछ समय से ऐसे मामले बढ़े हैं जिनमें भीड़ किसी न किसी बहाने एकत्रित होकर अराजकता फैलाने अथवा सरकारी कामकाज में अड़ंगा लगाने का काम करती है। यह हमारे नीति-नियंताओं के लिए गंभीर चिंता का विषय बनना चाहिए कि अराजक भीड़ केवल कानून हाथ में लेने का ही काम नहीं कर रही, बल्कि वह सरकारी कर्मियों, डॉक्टरों और यहां तक कि पुलिस को भी निशाना बना रही है। क्या इससे खराब बात और कोई हो सकती है कि कानून की रक्षक पुलिस ही भीड़ की अराजकता का शिकार हो जाए?यदि लोकतंत्र को भीड़तंत्र में तब्दील होने से रोकना है तो फिर भीड़ की हिंसा के सिलसिले को रोकना ही होगा। आवश्यक हो तो नए नियम-कानून बनाने में संकोच नहीं किया जाना चाहिए। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि इंदौर, आदिलाबाद और महाराष्ट्र में जिन जनप्रतिनिधियों ने गुंडागर्दी की उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

क्या यह अजीब नहीं कि जिन जनप्रतिनिधियों पर नियम-कानूनों के पालन का दायित्व है वे ठीक इसका उलट करने में लगे हुए हैं?

जरूरी यह है कि उन्हें अपने किए की सजा मिले और जल्द से जल्द मिले। आकाश विजयवर्गीय, कोनेरू कृष्णा और नीतेश राणे जैसे अराजक जनप्रतिनिधियों और उनके समर्थकों को सजा देकर ही यह संदेश दिया जा सकता है कि अराजकता को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या यह अजीब नहीं कि जिन जनप्रतिनिधियों पर नियम-कानूनों के पालन का दायित्व है वे ठीक इसका उलट करने में लगे हुए हैं? किसी को भी इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि वह भीड़ के सहारे अभद्र अथवा अराजक हरकतें करके बच निकल सकता है।